सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इंडिया

का मुख पत्र–(पाक्षिक)

मुख्य सम्पादक : प्रीतीश चन्दा

वर्ष 1 अंक 6 22 नवम्बर 1985 मूल्य 30 पैसे

यूनाईटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (लेनिन सारणी)

के 17 वें अखिल भारतीय सम्मेलन के प्रति तमाम देश के श्रमिक वर्ग में उत्साह की लहर

15 नवम्बर दिल्ली। राजधानी की दीवारों पर लगे पोस्टर और स्थान-स्थान पर लगे स्ट्रीमर (Streamer) नगरवासियों को किसी महत्वपूर्ण आयोजन की सूचना दे रहे हैं। यह आयोजन है, 21-23 नवम्बर 1985 को होने वाला यू. टी. यू. सी (ले.सा) का 17 वां अखिल भारतीय सम्मेलन। यह सूचना और भी अनेक माध्यमों से लोगों को मिल रही है, निश्चय ही वे माध्यम रेडियो, टी. वी. जैसे सरकारी प्रचार तंत्र नहीं हैं। केन्द्रीय सचिवालय जैसे सरकारी कार्यालय बहुल क्षेत्र हों या नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ पूर्ण रेलवे स्टेशन, हर स्थान पर संगठन के कार्यकर्ता सारा-सारा दिन डब्बा-संग्रह करके सम्मेलन के लिये अर्थ-संग्रह करते, पर्चा-वितरण करते व लोगों को सम्मेलन का महत्व समझाते देखे जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों व श्रमिक बस्तियों में घर-घर जाकर ये लोग सम्मेलन का महत्व समझाकर अर्थ-संग्रह में जुटे हैं। जब सहज और सौम्य ढंग से किसी प्रश्न के उत्तर में ये कहते हैं कि 'अपने लिये नहीं मांगते', 'सामाजिक कार्य है समाज को ही देना होगा', तो उनकी दृढ़ता संकल्प और विश्वास से अभिभूत होकर लोग प्रशंसनीय दृष्टि से उन्हें देखते हैं। नगरवासियों के लिये यह एक अभूतपूर्व अनुभव है। ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य के लिये इस प्रकार उनसे पहले तो किसी ने कुछ नहीं मांगा! वे इन कार्यकर्ताओं से तरह-तरह के प्रश्न करते हैं, उत्तर पाकर आश्वस्त होते हैं।

यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) के दिल्ली कार्यालय से सम्पर्क करने पर एक प्रवक्ता ने बताया कि यह सम्मेलन ऐसे समय होने जा रहा है जब देश का श्रमिक वर्ग गम्भीर आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। इस परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रवक्ता ने आशा व्यक्त की कि 21 नवम्बर 85 को फिरोजशाह कोटला मैदान में होने वाले खुले अधिवेशन और उससे पूर्व होने वाली नगर-परिक्रमा में लाखों मजदूर, कर्मचारी, ग्रामीण मजदूर और गरीब किसान भाग लेंगे। यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) से सम्बद्ध 700 यूनियनों के 3000 प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे। यह भी आशा की जा रही है कि सम्मेलन में सोवियत रूस, उ. कोरिया, बंगला देश व अन्य देशों के अनेक विशिष्ट भ्रातृ-प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। विश्व के अनेकों भ्रातृ-ट्रेड यूनियन संगठनों व देश के महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन केन्द्रों की ओर से लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं।

यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) दिल्ली प्रदेश की ओर से पिछले दो माह से सम्मेलन की जोरदार तैयारी चल रही है। सैंकड़ों नेता, कार्यकर्ता व वालंटियर दिन-रात अथाह परिश्रम कर सम्मेलन के लिये फंड-संग्रह, प्रचार कार्य व अन्य महत्वपूर्ण प्रबन्ध करने में जुटे हैं। ऐतिहासिक लाल किले के पीछे विजय घाट शान्ति वन से लेकर शान्तिवन तक के विस्तृत मैदान में विशाल शिविर का निर्माण कार्य शुरु हो चुका है, जिसमें 60,000 से अधिक लोगों के ठहरने का प्रबन्ध होगा। प्रतिनिधि सम्मेलन के लिये भी विशाल पंडाल इसी स्थान पर बन रहा है।

दिल्ली के जिन उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों में यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) से सम्बद्ध यूनियनें हैं, उनमें यूनियन के नेता और कार्यकर्ता जोर-शोर से प्रचार कार्य कर रहे हैं। ओखला औद्योगिक क्षेत्र के इलैक्ट्रानिक्स उद्योग में यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) से सम्बद्ध सशक्त यूनियनों ने इस क्षेत्र में इस दौरान अनेक सभाओं का आयोजन किया। कल 3 अक्तूबर को शायलोरा टी. वी. फैक्टरी के सामने वाले मैदान में मजदूरों की एक विशाल जनसभा हुई जिसमें सुप्रसिद्ध श्रमिक नेता और यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) के महासचिव कामरेड प्रीतीश चन्दा ने सम्मेलन के मुद्दों पर प्रकाश डाला। डी. टी. सी. मजदूर यूनियन, डी. टी. सी. कर्मचारियों में सम्मेलन का प्रचार करने में जी-जान से जुटे हैं। इसके अतिरिक्त शाहदरा-साहिबाबाद के इन्जीनियरिंग उद्योग में यू. टी यू. सी. (ले. सा.) से सम्बद्ध यूनियनें भी इस ऐतिहासिक कार्य में अपना योगदान देने में किसी से पीछे नहीं हैं। कर्मपुरा, नजफगढ़ व किशनगंज के औद्योगिक क्षेत्रों में भी कार्य जोरों से चल रहा है। गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत तथा बहादुरगढ़ जैसे दिल्ली के समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूर भी पूरे उत्साह से सम्मेलन की तैयारी के कार्य में जुटे हैं।

यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) के दिल्ली कार्यालय के अनुसार देश के अन्य भागों से भी सम्मेलन की तैयारी के विषय में उत्साहवर्धक समाचार मिल रहे हैं। सम्मेलन का मूल दस्तावेज दो महीने पहले ही जारी कर दिया गया था, ताकि इसमें दर्ज मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके।

हरियाणा के विभिन्न जिलों जैसे रोहतक, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, महेन्द्रगढ़, हिसार, इत्यादि स्थानों में व्यापक पैमाने पर जनसभाएं व विभिन्न प्रकार का प्रचार कार्य किया जा रहा है। हर महत्वपूर्ण स्थान पर दीवार-लेखन व पोस्टर दिखाई पड़ता है।

पंजाब से भी प्रचार कार्य की खबरें मिली हैं।

राजस्थान के कोटा, बूंदी, इन्द्रगढ़ क्षेत्र के खदान मजदूर, चीनी मिल मजदूरों व सूती मिल मजदूरों में सम्मेलन के प्रति पर्याप्त उत्साह है। सम्मेलन के मुद्दों को लेकर मजदूर आपस में चर्चाएं कर रहे हैं।

केरल के छः-सात जिलों में सम्मेलन को लेकर बड़ी-बड़ी सभाओं का आयोजन किया जा चुका है। प्रचार का कार्य जोरों पर है। समाचार मिला है कि यहां से लगभग 250 मजदूर सम्मेलन में भाग लेने के लिये आ रहे हैं।

तमिलनाडू के मद्रास व मदुरै के शहरी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों से खबर मिली है कि यहां के सेलम (Salem) स्टील फैक्ट्री व शिवाकाशी जैसे औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों में सम्मेलन के प्रति खूब उत्साह है।

आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल, अनन्तपुर तथा विजियानगरम इत्यादि क्षेत्रों से सम्मेलन की तैयारी की उत्साहवर्धक रिपोर्ट मिली है।

कर्नाटक में SUCI व AIDSO के नेतृत्व में बस-भाड़ा वृद्धि के विरोध में चल रहे आन्दोलन के बावजूद सम्मेलन का तैयारी कार्य जोरों पर है।

मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के श्रमिक यू. टी. यू. सी. (ले.सा.) से सम्बद्ध भेल लेबर यूनियन के नेतृत्व में सम्मेलन के लिए जी-तोड़ कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सागर व जबलपुर क्षेत्रों में कार्य तेजी से चल रहा है। सम्मेलन के मुद्दे मजदूरों में खूब चर्चित हैं।

महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) से सम्बद्ध यूनियनों के नेतृत्व में पथ-सभाएं और नुक्कड़ नाटक भी प्रचार कार्य का अंग बन गए हैं।

पूर्वी तथा प. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण कृषि मजदूरों में सम्मेलन के प्रति अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। यहां से हजारों मजदूरों व गरीब किसानों के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। सम्मेलन में उठाए जाने वाले मुद्दों में लोग रुचि ले रहे हैं।

उड़ीसा-बिहार की कोयला, लोहा, तांबा इत्यादि खदानों, जमशेदपुर (इस्पात नगर) के इस्पात कारखानों तथा सीमेंट उद्योग में यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) की सशक्त यूनियनें हैं। इन क्षेत्रों में दीवार-लेखन, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से जोर-शोर से प्रचार कार्य चल रहा है। इन दोनों प्रदेशों से लगभग 25,000

(शेष पृष्ठ 3 पर)

21—23 नवम्बर, 1985 को यू० टी० यू० सी० (लेनिन सरणी) का

अखिल भारतीय सम्मेलन

खुला अधिवेशन : 21 नव. सांय 3 बजे, फिरोजशाह कोटला मैदान

प्रतिनिधि सम्मेलन : 22-23 नवम्बर, लाल किले के पीछे

विश्व की पहली सफल सर्वहारा क्रांति

नवम्बर क्रांति जिंदाबाद

68 वर्ष पूर्व रूस में सर्वप्रथम सर्वहारा क्रान्ति सफलीभूत हुई थी। इस महान नवम्बर क्रान्ति के जरिये दुनिया में पहली बार मजदूर वर्ग की राजसत्ता का आविर्भाव हुआ था। मरणासन्न पूंजीवाद के इस युग में मानव-समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने हेतु सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक कार्य को पूरा करना कितना आवश्यक है; इस क्रान्ति ने इस बात के महत्त्व को सिद्ध कर दिखाया। इस क्रान्ति ने बुर्जुआ वर्ग के इस झूठे प्रचार का कि 'उत्पीड़ित मेहनतकश जनता मजदूरी की गुलामी (Wage slavery) करने और अपमान-जनक जीवन जीने को अभिशप्त है' भंडा फोड़कर इस दुष्प्रचार का मुंह-तोड़ जवाब दिया था कि; 'श्रमिक वर्ग को राजसत्ता पर अधिकार

सम्पादकीय

कर देश को चलाने की आशा भी नहीं करनी चाहिये'। महान नवम्बर क्रान्ति ने ठोस रूप में यह सिद्ध कर दिखाया कि यदि सर्वहारा वर्ग के पास उसकी अपनी ऐसी सही क्रान्तिकारी पार्टी हो, जो उन्हें क्रान्तिकारी सिद्धान्तों से शिक्षित कर सके तथा उन्नत सर्वहारा संस्कृति और नीति-नैतिकता के आधार पर सही मूल क्रान्तिकारी लाइन को लेकर उनका नेतृत्व कर सके तो वे पूंजीवादी शोषण की जंजीरों को तोड़ कर फेंक सकते हैं। इस युग निर्माणकारी क्रान्ति की शिक्षाएं उन्हीं के लिये अर्थपूर्ण हैं, जो अपने-अपने देश की ठोस परिस्थितियों के अनुसार इन शिक्षाओं को अपने व्यवहार और कार्य में ठोस रूप में ढाल सकते हैं। सर्वहारा के महान नेता कामरेड शिब-दास घोष ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सारतत्त्व को ग्रहण करते हुए एस. यू. सी. आई. का निर्माण किया तथा अपने देश भारत में इसे सर्वहारा क्रान्ति का नेतृत्व करने लायक बनाया। एस. यू. सी. आई. ही वह एकमात्र पार्टी है जो लोगों के जीवन के हर पक्ष से संबन्धित क्रान्तिकारी सिद्धान्त प्रदान करने की क्षमता रखती है, तथा पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रान्ति की सही मूल राजनीतिक लाइन प्रदान करती है। एस. यू. सी. आई. लोगों को सचेत करती है कि वे संसदवाद और कानून के घेरे (Parliamentarism legalism) में न फंस कर सर्वहारा नीति-नैतिकता और आदर्श के सशक्त आधार पर निचले स्तर तक जन-समितियों के रूप में अपनी निजी राजनीतिक शक्ति का विकास करें। पूंजीवाद विरोधी क्रान्ति की सटीक दिशा में सशक्त जनवादी आन्दोलन के द्वारा ही जनता की विकल्प राजनीतिक शक्ति को जन्म दिया जा सकता है। मात्र इसी रास्ते से जनता और समाज को मुक्ति के आकांक्षित लक्ष्य की ओर ले जाया जा सकता है।

आज जब पूंजीवादी समाज-व्यवस्था दिवालिया होकर लड़खड़ा रही है, ऐसे में संकटग्रस्त पूंजीपति वर्ग जनता पर चौतरफा हमला बोलकर, जी-जान से इस व्यवस्था की रक्षा करने में जुटा है। असहनीय आर्थिक बोझ, भ्रातृघाती जातीय व साम्प्रदायिक दंगे, मूलभूत मानवीय मूल्यों व आदर्शों का अपकर्ष; इन सबने मिलकर लोगों के जीवन को नरक-तुल्य बना दिया है। इस संकट का समाधान न कर पाकर, सत्ताधारी पार्टियां जनता के बढ़ते हुए आक्रोश का गला घोंटने की चेष्टा में लगी हैं और एक के बाद एक तानाशाही कानून बनाती जा रही हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां अपने चरित्र के अनुरूप ही जन-आक्रोश को संसदवाद-सुधारवाद के दायरे में सीमित रखने की चेष्टा करते हुए मरणासन्न पूंजीवाद की रक्षा में अन्तिम संबल का कार्य कर रही हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि नवम्बर क्रांति का मूल सिद्धान्त और विचार आज भी औचित्यपूर्ण है। ऐसी विकट परिस्थिति में एस. यू. सी. आई. ही वह एकमात्र पार्टी है जो संघर्ष और मुक्ति के झंडे को ऊंचा उठाए हुए है। इस पार्टी ने शोषित जनता को संगठित कर सशक्त जनवादी जनान्दोलन का निर्माण करने की दिशा में बीरतापूर्वक पहलकदमी की है। लोगों से एस. यू. सी. आई का आग्रह है कि, वे समझें कि, केवल सशक्त जन-वादी जनान्दोलन के बल पर ही देश में सम्पूर्ण फासीवाद लाने के बुर्जुवा षड्यन्त्र को चकनाचूर किया जा सकता है। आज लोगों के सामने यही एकमात्र रास्ता बचा है कि वे एस. यू. सी. आई द्वारा छेड़े गए जनवादी जनान्दोलन में शामिल होकर उसे मजबूती प्रदान करें। नवम्बर क्रांति की सर्वाधिक महत्त्व-पूर्ण सीख यही है।

द० अफ्रीका पर चोगम (CHOGM)

समझौता—धोखे का दस्तावेज

कामनवैल्थ देशों के मुखियाओं (CHOGM-Commonwealth Heads of Governments Meeting) की बैठक में द० अफ्रीका को लेकर एक समझौता हुआ है। प्रतीत होता है कि इस समझौते पर पहुंचने में भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह समझौता वास्तव में एक बहुत बड़ा ढोंग है। इस मीटिंग में द० अफ्रीका पर आर्थिक व व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की बड़ी-बड़ी बातें कही गईं, तथा अनेक प्रकार से शुभेच्छाएं भी प्रकट की गईं।

'प्रतिबंध' नाम के शब्द का न ही तो किसी औपचारिक प्रस्ताव में प्रयोग हुआ और न ही अन्य प्रकार इसका जिक्र किया गया।

अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों और भारत जैसे देशों के निहित स्वार्थों को बनाए रखने के लिए मतदान नहीं कराया गया। वस्तुतः इस तथ्य को स्वीकारा नहीं जा रहा है, उल्टे दिखावा यह किया जा रहा है कि कामनवैल्थ को टूटने से बचाने के लिये ही ऐसा किया गया।

समझौते में मात्र इस बात का उल्लेख है कि द० अफ्रीका को मिलने वाले नए सरकारी ऋणों पर रोक लगनी चाहिए। इस तरीके से तो बोथा सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकेगा।

यह बात सर्वविदित है कि पहले भी द० अफ्रीका पर तेल, परमाणु सामान तथा तकनीकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन इस प्रतिबंध का बार-बार उल्लंघन किया गया। यह भी एक सच्चाई है कि अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, प० जर्मनी जैसी साम्राज्यवादी शक्तियां ही नहीं बल्कि भारत जैसे देश भी दो मुंहे आचरण और धोखेबाजी के लिये अपराधी हैं। ब्रिटेन की 120-150 खरब डालर की रकम द० अफ्रीका में लगी है, और वहीं के 10 लाख लोग द० अफ्रीका में धनोपार्जन कर रहे हैं। अमरीका, कनाडा और प० जर्मनी की पूंजी भी वहां लगी है। भारत के भी व्यापारिक हित द० अफ्रीका से जुड़े हैं, अवरोध रूप में विमान सेवाओं, पर्यटन व तथाकथित सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर भी भारत का व्यापार चल रहा है। दस लाख भारतीयों के द० अफ्रीका में अच्छे सम्बन्ध हैं, और अनेकों को अफ्रीका की राष्ट्रीय धारा में स्थान मिले हुए हैं। ये सब देश मिलकर द० अफ्रीका में उपलब्ध सस्ते श्रम और विपुल तथा समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने में एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। ये सब शक्तियां द० अफ्रीका के लोगों और वहां के संसाधनों के बर्बर शोषण की सच्चाई को छुपाने के लिए ही द० अफ्रीका की अर्थव्यवस्था के प्रति चिन्तित होने का ढोंग करते हैं। इन साम्राज्यवादी शक्तियों के हितों और मंसूबों का सर्वाधिक घृष्टतापूर्ण पक्ष यह है कि ये वहां के आम लोगों में फूट डालने के लिये नस्लवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग वहां की जनता को धर्म और रंग के आधार पर विभा-जित कर उनकी एकता पर प्रहार करने का षड्यन्त्र कर रहे हैं, जिससे कि वहां की जनता अपने मुख्य शत्रु साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष न कर सके।

इस मीटिंग में कामनवैल्थ के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की एक छोटी सी कमेटी भी गठित की गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भी इस कमेटी के एक सदस्य हैं। इस कमेटी का कथित उद्देश्य है गैर-नस्लवादी, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के लिये 'हर ओर से होने वाली हिंसा को रोकने' तथा 'सभी रंगों, धर्मों व राजनीतिक मत वाले लोगों के बीच बातचीत की प्रक्रिया चालू करने की दिशा में' कदम उठाना। ब्रिटोरिया की नस्लवादी सरकार के राष्ट्रपति श्री बोथा ने इस प्रस्ताव को मानने से कोरम इंकार कर दिया। ये सब प्रयास ऐसे समय में किये जा रहे हैं, जब द० अफ्रीका के लोगों में राष्ट्रीय आजादी का उफान तेजी पर है। स्थिति इतनी विकट हो चली है कि दमनकारी बोथा सरकार भी गहरे संकट में फंसी दिखाई दे रही है।

द० अफ्रीका से श्वेत लोग तेजी से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं। यह देखते हुए फिलहाल बोथा सरकार ने ऋण-भुगतान पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय कवि बेंजामिन मोलोइस की फांसी ने आग में घी पड़ने जैसा काम किया है।

अतः यह समझौता नस्लवादी सरकार के बचाव का कार्य करते हुए, इस सरकार को तनाव कम करने के लिये पर्याप्त समय और अवसर देने की ही एक चाल है। हालांकि यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि यह समझौता द० अफ्रीका के लोगों के प्रति सहानुभूति के रूप में किया गया है। लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। निर्गुट सम्मेलन (NAM) के चेयरमैन श्री राजीव गांधी ने भी भरपूर दिखावा किया है। लेकिन यह कपट इतना पारदर्शी है कि इससे सही समझबूझ वाले और निष्पक्ष लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।

साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की शानदार परम्परा वाली भारत की जनता, भारत सरकार से मांग करती है कि वह कामनवैल्थ के साथ हर प्रकार का संबंध भंग करते हुए द० अफ्रीका के लोगों की जायज आकांक्षाओं का समर्थन करे। द० अफ्रीका के साथ चलने वाले हर प्रकार के छुपे व्यापार को बंद किया जाए। तथा इसी प्रकार के कदम उठाने के लिये अन्य देशों पर भी दबाव डाले। द० अफ्रीका के लोग निश्चय ही स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की कोई भी ताकत इतिहास-चक्र को उल्टा नहीं घुमा सकती। हमें अपनी घनिष्ठता और दोस्ती सही मायनों में प्रदर्शित करनी होगी; मात्र शब्दों में नहीं।

(पृष्ठ एक का शेष)

लोगों के सम्मेलन में भाग लेने का समाचार है। पहले से ही सम्मेलन कोष में पर्याप्त धन राशि भेजी जा चुकी है।

प. बंगाल में, जहां यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) अन्य सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से सापेक्ष रूप से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है, सम्मेलन की तैयारी का कार्य पूरे जोरों पर है। अकेले इस प्रदेश से 40,000 से भी अधिक लोगों के खुले अधिवेशन में शामिल होने की खबर है। पूरे प. बंगाल में सम्मेलन के मुद्दों पर जोरदार बहस चल रही है।

त्रिपुरा से भी लोग प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं।

इस सम्मेलन में देश के सभी प्रान्तों से भारी संख्या में श्रमिक आ रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं, उल्लेखनीय बात यह है कि महिला श्रमिक भी एक विशाल संख्या में भाग ले रही हैं।

औद्योगिक मजदूरों के अतिरिक्त देश के सर्वाधिक लांछित, शोषित, उत्पीड़ित, ग्रामीण गरीबों व कृषि मजदूरों में यू. टी. यू. सी. (ले. सा.) का संगठन सबसे अधिक व्यापक और सुदृढ़ है। यही वह एकमात्र केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन है जिसने सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित मजदूरों को संगठित करने की बात पर जोर दिया था। इस सम्मेलन में देहाती गरीबों की एक विशाल संख्या भाग लेगी। सभी महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे इस्पात, इन्जीनियरिंग, सड़क व अन्य परिवहन, सीमेंट, चमड़ा, चाय, कॉफी, काजू इत्यादि के श्रमिकों के अतिरिक्त गरीब खेतिहर मजदूर भी कंधे से कंधा मिलाकर उपस्थित होकर अपना-अपना योगदान देंगे।

इस सम्मेलन के अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर विचार किया जाएगा। 'परमाणु बम की धमकी, 'युद्ध और शांति की समस्या' तथा 'पूंजीवादी दुनिया का नया फासीवादी चेहरा', कुछ ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाएगा। भारतीय अर्थवाद किस प्रकार बहुराष्ट्रीय

यू०टी०यू०सी० (लेनिन सारिणी) का सम्मेलन

संस्थाओं के साथ हाथ मिलाकर देश में इन संस्थाओं को लूट की खुली छूट दे रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी मुद्रा एजेन्सियों से किस प्रकार भारत जनविरोधी निकृष्ट शर्तों पर ऋण प्राप्त कर रहा है, इन शर्तों को पूरा करने के लिये किस प्रकार केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारें रेल व परिवहन भाड़ा बढ़ा रही हैं, मजदूरी लागत कम करने के नाम पर किस प्रकार छंटनी चला रही हैं, इत्यादि कुछ अन्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी सम्मेलन में विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देश में लगभग आज कई हजार औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी हैं, तालाबन्दी के कारण हजारों मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, राजीव सरकार की कंप्यूटरीकरण की नई नीति के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर और भी सीमित हो जाने की सम्भावना तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों की गलत जनविरोधी अर्थनीति व बजट के चलते मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होना तथा मंहगाई का बेहिसाब बढ़ना इत्यादि मसलों पर भी सम्मेलन विचार करेगा।

सम्मेलन में देश के मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर पूंजीपति वर्ग के लगातार तेज होते जा रहे हमले, यूनियन बनाने व हड़ताल करने के अधिकार पर रोक लगने, ट्रेड यूनियन अधिकार छिनने इत्यादि समस्याओं पर विचार करते हुए आगामी समय में आवश्यक आन्दोलन की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 311 (2) (B) की व्याख्या करते हुए अपने ताजा प्रतिगामी फैसले से जिस प्रकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों व अन्य सभी कर्मचारियों को आत्मरक्षा व नैचुरल जस्टिस (Natural Justice) के अधिकार से वंचित कर दिया है, सम्मेलन इस पर भी विचार करेगा।

आशा है कि यह सम्मेलन आगामी दिनों में मजदूर आन्दोलन के लिये सही दिशा का निर्धारण कर इस आन्दोलन को और भी उन्नत स्तर में ले जाने में सफल होगा।

कवि बेंजामिन मोलोइस को फांसी दिये जाने के विरोध में केन्द्रीय कमेटी का प्रस्ताव

21-10-85

द० अफ्रीका के नस्लवादी बर्बर शासकों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के कवि बेंजामिन मोलोइस को फांसी पर लटका कर, मानवता के विरुद्ध पहले से किये गए अपने अपराधों की सूचि में एक और अपराध जोड़ लिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अधिकार द० अफ्रीका के लोगों का ग्रहणीय अधिकार है। मूलभूत मानव अधिकारों के विरुद्ध किये गए इस हमले और मानव सभ्यता के इस घोर अपमान की निन्दा शब्दों में नहीं की जा सकती।

विश्व जनमत की घोर अवहेलना करते हुए नस्लवादी शासकों ने इस कवि की हत्या कर इस बात की पुष्टि की है कि उसकी पीठ पर अमरीका और ब्रिटेन जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों का हाथ है, वैसे ये शक्तियां दुनिया के लोगों को ठगने के लिये मानव अधिकारों के प्रति आस्था का ढोंग रचने में कोई कसर नहीं उठा रखतीं।

यदि देशभक्ति के कवि को आज़ादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है, तो विश्व के विवेकी एवं जागरुक लोगों को द० अफ्रीका में बर्बर नस्लवादी शासन का खात्मा करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाने होंगे। जिससे कि द० अफ्रीका के लोगों को राष्ट्रीय आज़ादी, और अपने नैसर्गिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये अपने सर्वश्रेष्ठ बेटे-बेटियों की और अधिक बलि न देनी पड़े।

सरकार की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के विरोध में ए.आई.डी.एस.ओ. के आह्वान पर आन्दोलन

राजीव सरकार की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति, शिक्षा के अर्थ और लक्ष्य को न केवल झुठलाती है बल्कि शिक्षा को आम लोगों की पहुंच से बाहर ले जाने का एक घिनौना षड़यन्त्र है।

आल इंडिया डैमोक्रेटिक स्टूडेंटस आरगे. (AIDSO) ने इस नीति के विरोध में देशव्यापी स्तर पर मीटिंगों, सेमिनारों, वाद-विवाद व अन्य ढंग से 'शिक्षा बचाओ दिवस' मनाने का कार्यक्रम लिया। यह कार्यक्रम दिल्ली, प० बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यू० पी०, बिहार, असम, उड़ीसा व अन्य प्रदेशों में सफलतापूर्वक चलाया गया। सभी स्थानों पर छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों व आम लोगों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा इस नीति के रूप में शिक्षा पर होने वाले आसन्न हमले के प्रति चिन्ता व्यक्त की।

उड़ीसा में 'शिक्षा बचाओ दिवस' 1 अक्तूबर को मनाया गया। इस दिन राज्य सचिवालय के सामने एक विशाल रैली आयोजित की गई। लखनऊ (उ० प्रदेश) में छात्रों का एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो राज्य विधान सभा के पास जा कर एक सभा में परिणत हो गया। कलकत्ता में 1 अक्तूबर को 'शिक्षा बचाओ दिवस' मनाया गया। इस दिन एक विशाल जुलूस राजभवन तक पहुंचा और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय के पास जाकर एक सभा में बदल गया। 5 अक्तूबर को द्वारभंग हाल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डा० सुशील मुखर्जी, विश्वभारती के पूर्व उपकुलपति डा० अमलन दत्ता, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डा० अजीत साहा व अन्य विशिष्ट शिक्षाविदों सहित अनेक प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया।

30 सितम्बर को दिल्ली में छात्रों, अभिभावकों व विशिष्ट शिक्षाविदों को लेकर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया।

आंध्र प्रदेश में ललितपुर कला परिषद् अनन्तपुर में 19 अक्तूबर को एक बड़ी सभा आयोजित की गई।

बंगलोर में 'शिक्षा बचाओ दिवस' पर छात्रों का एक विशाल जुलूस निकाला गया तथा 1 अक्तूबर को सम्मेलन का आयोजन किया गया।

केरल में राज्य स्तर पर 'शिक्षा बचाओ कमेटी' का गठन किया गया है। 9 जुलाई को समस्त केरल स्तर पर विरोध दिवस मनाया गया। इस दिन छात्रों के बहिष्कार के कारण अनेक स्कूल और कालेज बन्द रहे। कोचिन में 1 अक्तूबर को 'शिक्षा बचाओ दिवस' मनाया गया।

कैलिकट में 29 जुलाई को कैलिकट विश्वविद्यालय सीनेट के सामने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

28 वें भारतीय श्रम सम्मेलन (त्रिपक्षीय) के ऊपर

कामरेड प्रीतीश चन्दा की प्रतिक्रिया

—भारत सरकार ने 28वें भारतीय श्रम सम्मेलन में यू० टी० यू० सी० (लै० सा०), इन्टक, एच०एम०एस० और बी०एम०एस० से अपने प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया है। सीटू और एटक को अपने प्रेक्षक भेजने को कहा गया है।

11 नवम्बर, दिल्ली। भारत सरकार द्वारा आगामी 25-26 दिसम्बर को आयोजित किये जाने वाले 28वें भारतीय श्रम सम्मेलन (त्रिपक्षीय) पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज यहां यू. टी. यू. सी. (लै. सा.) के महासचिव व सुप्रसिद्ध श्रमिक नेता कामरेड प्रीतीश चन्दा ने कुछ संवाददाताओं को बताया कि इस सम्मेलन के द्वारा सरकार, श्रमिक वर्ग की आवाज को महत्त्व देने का ढोंग रच रही है। जबकि असलियत यह है कि भारत सरकार मजदूर वर्ग की आवाज को तनिक भी महत्त्व नहीं देती। उल्टे एक ओर तो सरकार जनता के जनवादी अधिकारों और विशेषकर मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर दिन प्रतिदिन निर्मम प्रहार कर रही है और दूसरी ओर मजदूर वर्ग के सामने कुछ टुकड़े फेंक कर उन्हें भ्रमजाल में फंसाए रखना चाहती है। पश्चिम के पूंजीवादी देशों की शर्तों पर सरकार इस तरह श्रमिक वर्ग को धोखे में रखकर उन्हें मूर्ख बनाते हुए उनके संघर्ष की धार को कुन्द कर देना चाहती है। यद्यपि इस सम्मेलन का आयोजन अनियमित ढंग से किया जा रहा है, फिर भी यू. टी. यू. सी. (लै. सा.) यह उचित समझती है कि इस सम्मेलन में रह कर अन्दर से श्रमिकों की आवाज को बुलन्द किया जाए। सरकार जो भी श्रमिक विरोधी नीतियां बनाने का प्रयास करेगी, यू. टी. यू. सी (लै.सा.) निश्चय ही गौरवपूर्वक इनका विरोध करते हुए सम्मेलन में प्रतिवाद का स्वर ऊंचा करेगी। कामरेड प्रीतीश चन्दा ने विश्वास व्यक्त किया कि देश का श्रमिक वर्ग सरकार और मालिकों की इन श्रमिक विरोधी नीतियों को चुपचाप रहकर स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए यू. टी. यू. सी. (लै. सा.) ने मांग की है कि इस सम्मेलन में श्रमिकों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

कामरेड चन्दा ने आगे बताया कि यू. टी. यू. सी. (लै. सा.) ने अपने 18 अक्तूबर के पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रम मन्त्री के समक्ष इस बात पर अपना विरोध प्रकट किया है कि उनके मन्त्रालय ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से बातचीत किए बिना ही इस सम्मेलन का एजेन्डा (agenda) तैयार कर लिया है। क्योंकि इस एजेन्डे में श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया गया है, अतः यह एजेन्डा अपर्याप्त है। इस पत्र द्वारा निम्नलिखित मुद्दों को एजेन्डे में शामिल करने पर जोर दिया गया है :—

1) अनेकों औद्योगिक इकाइयों में चलने वाले अभूतपूर्व ले-आफ, तालाबन्दी और कारखाना बन्दी-ऐसी इकाइयों को फिर से खोलने की आवश्यकता और काम से निकाले गए मजदूरों को फिर से काम देना।
2) बेरोजगारी की बढ़ती समस्या।
3) मुद्रास्फीति और मंहगाई।
4) ट्रेड यूनियन अधिकारों का विस्तार।
5) सरकारी कर्मचारियों को नेचुरल जस्टिस के अधिकार की गारंटी देने के लिए संविधान संशोधन द्वारा धारा 311 (2) (B) को समाप्त करना।
6) बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारियों को काम से निकालने से उत्पन्न समस्या।
7) कंप्यूटरीकरण के कारण रोजगार-अवसरों के और भी संकुचित होने की समस्या।
8) राष्ट्रीय वेतन नीति (Wage Policy)
9) असंगठित क्षेत्र में कृषि मजदूरों और कर्मचारियों की समस्या (मजदूरी तथा काम मिलने की गारन्टी)
10) नौकरी की सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा।
11) महिला श्रमिकों की समस्या।
12) सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) का अधिकार।
13) ट्रेड यूनियनों की मान्यता एवं प्रतिनिधित्व।

औद्योगिक सम्पर्क के सम्बन्ध में कामरेड प्रीतीश चन्दा ने बताया कि पूंजीवादी दुनियां में जिन औद्योगिक सम्पर्क सम्बन्धी मान्यताओं का आदर किया जाता है, भारत में उन मान्यताओं को भी पैरों तले कुचला जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कन्वेंशन्स (conventions); संगठन बनाने के अधिकार की सुरक्षा के लिये एसोसिएशन की स्वतन्त्रता की 1948 की कन्वेंशन संख्या 87 और सामूहिक सौदेबाजी संगठित करने के अधिकार की 1948 की कन्वेंशन संख्या 98 को भारत सरकार ने अभी तक न तो स्वीकार किया है न ही उन्हें अपने देश में लागू किया है। यू. टी. यू. सी. (लै. सा.) पिछले लम्बे अर्से से मांग कर रही है कि :-

1) ट्रेड यूनियनों को प्लान्ट/उद्योग स्तर पर मान्यता हासिल होनी चाहिये तथा

प्रतिनिधि यूनियन का पता लगाने के लिये प्लान्ट के सभी श्रमिकों द्वारा गुप्त मतदान (secret ballot) कराया जाना चाहिए। समझौते में उन सभी यूनियनों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें मतों का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होता है। 50% से अधिक मत पाने वाली यूनियन को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिये।

2) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) व राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (त्रिपक्षीय) सहित सभी वैधानिक तथा अन्य बोर्डों और समितियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्यता की जांच जनवादी व वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिये। सदस्यता की चेकिंग के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की राय के आधार पर एक निष्पक्ष अथारिटि का गठन किया जाना चाहिये।
3) हड़ताल व जायज आन्दोलन के अधिकार की गारन्टी दी जाए तथा इन अधिकारों पर लगाए गए ESMA सहित सभी प्रतिबन्ध व रुकावटें हटाई जाएं।
4) सामूहिक सौदेबाजी का पूरा मौका दिया जाए। वेतन व अन्य संबंधित मसलों का निपटारा सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से किया जाए न कि वेज बोर्डों द्वारा।
5) कुछ ट्रेड यूनियनों का पक्ष लेने उन्हें बढ़ावा देने तथा अन्यों के साथ भेदभाव बरतने की सरकारी नीति समाप्त की जाए।

कामरेड चन्दा ने कहा कि जब तक उक्त मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा औद्योगिक सम्पर्क में सुधार की कोई सम्भावना नहीं है।

'सम्पूर्ण औद्योगिक शांति' 'कामबन्दी का खात्मा' तथा 'उत्पादन' व 'उत्पादकता' में तेजी लाने की बातों के पीछे संकटग्रस्त पूंजीवाद व सरकार का लक्ष्य अधिकाधिक श्रमिक विरोधी नीतियों को अपनाना है। ये सब बातें एकदम खोखली हैं, क्योंकि मालिकों का मकसद ही है किसी भी रास्ते अतिलाभ (Superprofit) अर्जित करना फिर चाहे इसके लिए उन्हें मजदूरों को अधभूखा-अधनंगा रखना पड़े, चाहे मिलबंदी व तालाबंदी द्वारा लाखों लोगों को काम से हटाना पड़े। मालिक कभी भी इन बातों को लेकर अपना सर नहीं खपाते। उत्पादन बढ़ाना मजदूरों के नियन्त्रण में नहीं है। क्योंकि अपने अतिलाभ के उद्देश्य से मालिक लोग ही उत्पादन-योजनाएं तय करते हैं। ऐसे में सरकार की नीति है, मालिकों को मक्खन और मजदूरों को डंडा। भारत सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आगामी दिनों में सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों की ओर साफ इशारा करता है।

बढ़ती बेरोजगारी पूंजीवादी दुनिया की आम प्रक्रिया

भारत जैसे विकासशील अथवा अविकसित देशों में हो रही बेरोजगारी ने विकसित पूंजीवादी देशों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ज्यों-ज्यों विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का संकट तीव्र होता जा रहा है, वैसे ही बेरोजगारी की स्थिति भी विकट होती जा रही है। निम्नलिखित आंकड़ों से तो यही सिद्ध होता है।

पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी

काम करने में सक्षम जनसंख्या के प्रतिशत रूप में

देश	1970	1975	1980	1985
अमरीका	5.0	8.3	7.0	7.3
कनाडा	अनुपलब्ध	6.9	7.5	10.9
इटली	3.1	5.8	7.4	12.9
फ्रांस	1.2	4.1	6.3	10.3
प० जर्मनी	0.8	3.6	3.0	9.4
जापान	1.1	1.9	2.0	2.4
इंग्लैंड	2.2	4.7	7.0	13.1

स्रोत : जून 1985 का इकोनोमिस्ट (लन्दन)

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर आफ इंडिया (एस.यू.सी.आई) की ओर से कामरेड ज्ञानसिंह द्वारा 4/11772 करोल बाग, दिल्ली - 5 से सम्पादित व प्रकाशित तथा सोलंकी प्रिंटर्स, बी-2633 मेन बस स्टैंड, शिवगर, दिल्ली - 35 से मुद्रित